

SHRI SURESH KALMADI : Will you appoint a committee to go into this question ?

(Interruptions)

SHRI R. VENKATARAMAN : This should not go on record.

SHRI SURESH KALMADI : I am asking whether some of these accidents are not due to sabotage. You say that this should not go on record. How can you say that ? Earlier also, when I raised the Calling Attention, I mentioned this.

SHRI R. VENKATARAMAN : I have nothing more to answer.

(Interruptions)

SHRI SURESH KALMADI : Do you mean to say that sabotage is such a simple thing that you cannot answer this ? I am walking out in protest.

[At this stage, the hon. Member left the Chamber]

SHRI R. VENKATARAMAN : Sir, finally, I wish to state that whatever the members have said in regard to the number of aircraft, the make of the aircraft and so on, have been on their own responsibility. Government does *not* confirm any of the statement which has been made by any hon. Member. These things have been said by them on their own responsibility. These may be borne out of guess or these may be borne out of their mental imagination, a flight of their imagination. But so far as Government are concerned, they do not, I repeat, they do not confirm any of the things which have been said by the hon. Members here. The mere fact that I am not specifically denying every one of these things should not be deemed to be or misunderstood to be an acceptance of these things.

The last point is, so far as sabotage is concerned we have no information and if the hon. Member gives any information, "we will investigate."

Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
The discussion is over

The House then adjourned for lunch at twenty hour minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty-seven minutes past two of the clock. The Vice-Chairman, (Shri R. R. Morarka) in the Chair.

REFERENCE TO THE REPORTED INCREASE IN POWER RATES BY THE U.P. STATE ELECTRICITY BOARD

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब खरीफ की फसल पूरी खराब हो चुकी है, काहीं अत्यधिक वर्षा हुई तो काहीं पर बहुत कम पानी पड़ा है, जिसके कारण एक तरफ सूखा हुआ और दूसरी तरफ बाढ़ आई। खरीफ का उत्पादन करीब 20 लाख टन उत्तर प्रदेश में कम हुआ है इसको बढ़ाने के लिए जो किसानों के सामने समस्या है उसको देखते हुए वह रबी की फसल को अच्छे तरीके से मेहनत करके बढ़ा नहीं सकता। उनके सामने जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने के लिए जब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक वह बढ़ा पाना सम्भव नहीं है। लेकिन उसके सामने जो सबसे पहली समस्या

[श्री घनश्याम सिंह]

है वह खरीफ की फसल खराब होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल हो गई है, उसके पास धन नहीं है। दूसरे चीनी मिलों ने उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना तो ले लिया है लेकिन अभी तक उनका पैसा भुगतान नहीं करने के कारण वह भी पैसा उनके पास नहीं होने के कारण वह कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों रबी की पैदावार के वक्त वेशुमार बरसात हुई जिसके कारण गेहूँ की फसल खराब हो गई थी जिसकी वजह से बीज का अभाव आज किसानों के सामने है। तो आज शासन को इन सब चीजों की व्यवस्था करनी होगी, तभी उत्तर प्रदेश के किसान अपनी रबी की फसल की पैदावार बढ़ा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात विशेष रूप से उल्लेख करनी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। वह यह है कि पानी की समस्या से जहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ पर नलकूपों से जो बिजली आजकल उत्तर प्रदेश में मिल सकती है वहाँ चाहे उन्होंने कहा है कि 3 घंटे या 4 घंटे बिजली मिलती है वैसे कहा गया है कागज में कि 6 घंटे मिलती है लेकिन उसमें इतनी बाधाएँ हैं जिसके कारण लगातार बिजली न मिलने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने दो तीन दिन पहले यह लिया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने अभी दो दिन पहले बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि 9 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों पर खास तौर से 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है और 15

हार्सपावर के ऊपर 22.5 रुपये कर दिया गया है जिसका सीधा व्यय किसानों पर पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि किसान ही इससे प्रभावित हैं सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो मैं उनको बढ़ाने के कारणों और उसके निराकरण के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को प्रति वर्ष काफी घाटा हो रहा है। जिसको पूरा करने के लिये या कम करने के लिये यह विद्युत की दर बढ़ाई गई है। जब राज्य विद्युत परिषद् के कार्यकलापों की तरफ ध्यान दिया जाये तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पर एवाइडेन्स लासेज हैं जिन को दूर किया जा सकता है। ऐसी जो हानि हो रही है उसके इम्प्रूवमेंट की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जो चोरी होती है उसको चैक नहीं किया जाता है। पुअर मेटेनेंस है जिसके कारण विद्युत गृह ठीक तरीके से नहीं चल पाते हैं। दूसरे इन्फिशियेंट अपरेशन की वजह से भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वहाँ ओवर स्ट्राफिंग है जिसकी वजह से कास्ट ज्यादा पड़ती है। विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता का सवाल है जिसे उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। कहने की मंशा यह है कि जो हम 18 से 30 परसेंट तक लासेज करते हैं विद्युत उत्पादन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम निगाह डालें तो केवल एक आइटम पर शायद 15 करोड़ रुपये की हानि को कम किया जा सकता है। जो कि चोरी की है। जहाँ तक पूअर मेटेनेंस का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूँ कि भरभरत के लिये, वहाँ के इंजीनियर ने ऐसा कर रखा है कि उनकी खरीद न करके ऐसा स्टाफ खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरे इन्फिशियेंट अपरेशन का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ।

मैं अलौगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ । वहाँ पर हरदोई गंज में विद्युत गृह है वहाँ पर सन् 77 में आपने सुना होगा कि एक धमाका हुआ था, विद्युत गृह में विस्फोट हो गया था । सन् 77 से आज तक वह विद्युत गृह चालू हालत में नहीं किया गया है । वहाँ करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । यह हमारी इन्फ्रिज-येंसी की दशा है । चूँकि विद्युत गृह में भी यही हुआ । वहाँ के कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके कारण से विस्फोट हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ । ओवर स्टॉफिंग की के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ । जो नाम्स हैं शासन के उन नाम्स के अनुसार इंस्टाल्ड कैपैसिटी 7.5 व्यक्ति पर मैगावाट रखने का है जबकि इसके विनरीत 12.8 व्यक्ति पर मैगावाट रखे जाते हैं जिससे करीब 18 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो अतिरिक्त लगे हुए हैं जिनकी वहाँ आवश्यकता नहीं है । मेरी मंशा यह नहीं है कि उन कर्मचारियों को निकाल दिया जाये । मेरी मंशा यह है कि जो हम आगे पावर हाउस लगाने जा रहे हैं उनमें उनको समाया जा सकता है । इस तरीके से जो प्रतिमाह करोड़ों रुपये बेतन के रूप में खर्च किये जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है । जहाँ तक विद्युत गृहों की क्षमता और उपयोग का प्रश्न है मैं आपको थोड़ा सा ओवरा विद्युत गृह के बारे में बता दूँ । वहाँ की इंस्टाल्ड कैपैसिटी साढ़े तेरह सौ मैगावाट की है । इसमें केवल विद्युत उत्पादन 500 मैगावाट का हो पाता है । इसी के बगवर् में रेणुकुट में जो हिंडालको वालों का प्राइवेट विद्युत गृह है वहाँ पर 90 परसेंट उत्पादन होता है । ये चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर कदम रखा जाये, उनकी तरफ ध्यान दिया जाये तो राज्य विद्युत परिषद् में जो घाटा

हो रहा है उसको कम किया जा सकता है और जो भार आज किसानों पर बढ़ाया जा रहा है उस पर विचार किया जा सकता है । मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि 28 जून 82 को यह विद्युत गृह है जिसके लिये उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् ने दर बढ़ाते वक्त यह घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया था उस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ । हिन्दुस्तान में दो जुलाई को निकला था कि यह जानकारी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य मंत्री ने संवाददाताओं को दी । उन्होंने कहा कि परिषद् ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की स्वीकृति के बिना किया था । सरकार का विचार है कि इस निर्णय से जनता पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा । इसलिये जो निर्णय जून में लिया गया था रद्द कर दिया गया । बाद में इसमें कहा है और बताया गया है—परिषद् के अधिकारियों ने बिजली की दरों में वृद्धि के लिये पहले से ही एक प्रस्ताव भेजा था । लेकिन मुख्य मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया था । राज्य विद्युत परिषद् अपनी क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने, प्रशासन की शिथिलता तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बड़ा घाटा हो रहा है । परिषद् पर अभी तक कुल मिलाकर 2 हजार चार सौ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन यह करीब 250 करोड़ वार्षिक घाटे पर चल रहा है । मेरे कहने की मंशा सिर्फ यह है कि ये सब चीजें ऐसी हैं अगर इन पर चैक किया जाये तो घाटे को कम किया जा सकता है । एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करूँगा कि जो निर्णय विद्युत दर बढ़ा कर, गरीब किसान तो बैसे परेशान है, सूखे से और दैवी आपत्ति से और दूसरे बहुत से कारणों से, उस पर 50 परसेंट टैक्स

[श्री घनश्याम सिंह]

बढ़ाया गया है इसका औचित्य कोई प्रतीत नहीं होता। इसलिये आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और अपने लासेज को कम करने के लिये और दूसरे बहुत से कदम उठाये।

REFERENCE TO THE REPORT -
ED POLICE RAIDS ON THE
OFFICES OF THE INDIAN
NATION' AND ARYAVARTA'

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार):
उपसभाध्यक्ष महोदय, आज टाइम्स आफ इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित कर देने वाला समाचार दखने को मिला। वह समाचार यह है कि बिहार में दो समाचार-पत्रों, इंडियन नेशन और आर्यावर्त के आफिस में पुलिस की और से एक महीने में दो बार रेड्स की गई हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ है जिसमें पुलिस को रेड करने से मना किया गया है। आप जानते हैं कि इंडियन नेशन और आर्यावर्त में चीफ मिनिस्टर, बिहार की ओर से मनका गांधी को जो यह पत्र लिखा गया था कि प्रो. रामनाथ सिंह को बिहार में संजय मंच का अधिकारी बनाया जाय, उसको फोटो स्टेट कापी छापी गई थी। यद्यपि यह बात सिर्फ इंडियन नेशन और आर्यावर्त में ही नहीं छपी थी बल्कि टाइम्स आफ इंडिया, आव-जरवर में भी छपी थी, लेकिन रेड सिर्फ इंडियन नेशन और आर्यावर्त के आफिस में की गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कल मना किया था और यह कहा था कि इंडियन नेशन और आर्यावर्त के एडिटरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट के फैसले को इसमें रिजर्वेट कर दिया गया था। इस बीच में पटना में रात्री में यह रेड हुई है। यह रेड इसलिए हुई कि इंडियन नेशन और आर्यावर्त में एक रिपोर्ट छपी कि एक सरकारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो नवादा की नजदीक हुआ है और जिसमें डाइरर मर गया है। उसमें यह भी कहा गया कि शायद ये लोग मुख्य मंत्री के संबंध के लोग थे। इस समाचार को छपने

के बाद जब कांटेक्ट किया गया तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया कि यह समाचार गलत है। इस गाड़ी में मरे कोई संबंधी नहीं थे। इसके बाद यह बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। परन्तु दूसरे एक व्यक्ति ने जो उसी डाइरर के नाम का था, उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, जिन्दा हूँ। यह समाचार गलत है। इंडियन नेशन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और यह सूचना दी कि वह आदमी इसी नाम का है और वह मरा है, यह सही समाचार है। जब यह समाचार छापने के लिए रात्री में तैयार किया जा रहा था, उसका प्रूफ पंज तैयार हो रहा था तो यह रेड की गई जिसमें यह कहा गया कि पटना में एक एफ. आई. आर. पुलिस में लिखाई गई है जिसमें उस व्यक्ति ने यह कहा है कि वह मरा नहीं है, लेकिन इस समाचार के छपने से उसको मेटल टारचर हुआ है। सिर्फ इस दफ. आई. आर. के ऊपर यह रेड कर दिया गया और सारे कामज ले लिये गये। इस संबंध में जो रिपोर्ट छपी है उसको मैं पढ़ देता हूँ :-

"Mr. Diria Nath Jha, Editor of the *Indian Nation* said the State Government was adopting crude methods to terrorise the staff 'j'f the newspaper. , Never , before had the State Government been so vindictive."

इस तरह से बिहार में हालत चल रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक ओर तो सारे हिन्दुस्तान में बिहार प्रेस बिल के कारण, बल्कि सारे विश्व में, हल्ला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह जोर-जबरदस्ती की जा रहो है। अगर कोई समाचार गलत छपा है तो सरकार उसका कंट्रिब्यूशन दे सकती थी और उसके बाद भी कोई उस समाचार को छापता तो कोई कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन इस प्रकार से जोर-जबरदस्ती करना गलत है।

श्री शिव चन्द्र भा (बिहार): इस तरह की बात बिल्कुल गलत है। इस मामले की सी. बी. आई. से जांच करवाही जानी चाहिए।